प्रधानमंत्री-इलेक्ट्रिक बस सेवा

प्रिलिम्स के लिये:

प्रधानमंत्री-इलेक्ट्रिक बस सेवा, इलेक्ट्रिक बसें, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, ई-मोबिलिटी, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ग्रीनहाउस गैस

मेन्स के लिये:

प्रधानमंत्री-इलेक्ट्रिक बस सेवा, धारणीय गतिशीलता और ग्रीनहाउस गैस कटौती में इसका महत्त्व

चर्चा में क्यों?

भारतीय मंत्रिमंडल ने "**पी.एम.ई-बस सेवा अथवा प्रधानमंत्री-इलेक्ट्रिक बस सेवा**" योजना को मंज़ूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य**सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से 10,000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करके शहरों में बसों के संचालन को बढ़ावा देना** है।

प्रधानमंत्री-इलेक्ट्रिक बस सेवा:

- **परिचय:**
  - इसका उद्देश्य **शहरी परिवहन दक्षता में वृद्धि करना और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा** देना है।
- **खंड A: सिटी बस सेवाओं में वृद्धि करना (169 cities):**
  - यह खंड सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत **10,000 ई-बसों द्वारा शहरी परिवहन को सुदृढ़ करने हेतु** समर्पित है।
  - यह योजना इलेक्ट्रिक बसों के **प्रभावी संचालन के लिये इलेक्ट्रिक बसों हेतु सबस्टेशन जैसे महत्वपूर्ण विद्युत बुनियादी ढाँचे के निर्माण के अतिरिक्त बस डिपो के बुनियादी ढाँचे के निर्माण अथवा उन्नयन की आवश्यकता** को चिह्नित करती है।
- **खंड B: हरित शहरी गतिशीलता पहल [Green Urban Mobility Initiatives (181 शहर)]:**
  - इस खंड में बसों की **प्राथमिकता बढ़ाना, बुनियादी ढाँचे में सुधार,** मल्टीमॉडल इंटरचेंज सुविधाएँ उपलब्ध करना, **नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (National Common Mobility Card- NCMC)-बेस्ड ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम** लागू करना और आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढाँचे का निर्माण शामिल है।
  - **इस योजना का लक्ष्य** इन टिकाऊ प्रथाओं को एकीकृत करके **शहरी गतिशीलता परिदृश्य को बदलना है।**
- **लक्षित जनसंख्या और पहुँच से वंचित क्षेत्र:**
  - यह योजना 2011 की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर **तीन लाख और उससे अधिक की आबादी वाले शहरों** को शामिल करेगी।
  - इस व्यापक दृष्टिकोण में **केंद्रशासित प्रदेशों की सभी राजधानियाँ,** देश के **उत्तर पूर्वी** हिस्से के **क्षेत्र** और **पहाड़ी राज्य** शामिल हैं।
  - इस योजना का एक महत्त्वपूर्ण आकर्षण **संगठित बस सेवाओं की कमी वाले शहरों पर इसका ध्यान** केंद्रित करना है तथा शहरी गतिशीलता अंतर को कम करना है।
- **संचालन एवं सुविधा:**
  - इस योजना का परिचालन पहलू, नियुक्त बस ऑपरेटरों को भुगतान करते समय बस सेवाओं को प्रबंधित करने तथा बनाए रखने की **ज़िम्मेदारी राज्यों और शहरों पर** डालता है।
  - केंद्र सरकार की भूमिका **योजना में उल्लिखित सब्सिडी** प्रदान करके इन कार्यों को सुविधाजनक बनाना और इनका समर्थन करना है।

योजना का महत्त्व:

- **रोज़गार के अवसर:**
  - इस योजना से 45,000 से 55,000 लोगों के रोज़गार की अनुमानित सीमा के साथ प्रत्यक्ष रोज़गार अवसर बढ़ने का अनुमान है।
  - यह बढ़ावा सिटी बस संचालन में इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती से होगा, जो शहरी गतिशीलता की जरूरतों को पूरा करते हुए आर्थिक विकास में योगदान देगा।
- **ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देना:**
  - यह ई-मोबिलिटी को अपनाने के लिये प्रेरित करती है, जो अपेक्षित मीटर के पीछे विद्युत के बुनियादी ढाँचे के लिये व्यापक समर्थन पर

आधारित है।
    - इसके अलावा **शहरों को [ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल](#) के हिस्से के रूप में महत्त्वपूर्ण चार्जिंग के** बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये समर्थन प्राप्त होगा।
    - यह समग्र दृष्टिकोण न केवल ऊर्जा-कुशल इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने में तेज़ी लाता है**बल्कि ई-मोबिलिटी क्षेत्र में नवाचार को भी बढ़ावा देता है।**
- **पर्यावरणीय प्रभाव और GHG में कमी:**
    - विद्युत गतिशीलता की ओर बदलाव से बड़े पर्यावरणीय लाभ होने का अनुमान है।
    - ध्वनि और वायु प्रदूषण को कम करने के साथ कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाकर, यह योजना व्यापक स्थिरता लक्ष्यों को हासिल करेगी।
    - बस-आधारित सार्वजनिक परिवहन के बढ़ते उपयोग से भी एक बदलाव आएगा, जिससे [ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन](#) में कमी आएगी।

ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिये सरकारी पहल:

- इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाना और विनिर्माण करना (FAME) योजना II
- नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (NEMMP)
- परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन
- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना
- वाहन स्क्रैपेज नीति
- गो इलेक्ट्रिक अभियान

आगे की राह

- "पी.एम.-ईबस सेवा" योजना **टिकाऊ शहरी गतिशीलता और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने में एक महत्त्वपूर्ण पहल** है।
- **प्रत्यक्ष रोज़गार सृजन, बुनियादी ढाँचे के विकास और पर्यावरण संरक्षण तक विस्तृत अपने बहुआयामी दृष्टिकोण** के साथ, यह योजना **लचीली एवं पर्यावरण-अनुकूल शहरी परिवहन प्रणाली** बनाने के लिये **भारत की प्रतिबद्धता** का उदाहरण प्रस्तुत करती है।
- इस **दूरगामी सोच वाली रणनीति** का शहरी विकास और पर्यावरण प्रबंधन दोनों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pm-ebus-sewa